



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक ९]

शनिवार, जुलै १९, २०१४/आषाढ २८, शके १९३६

[पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सामान्य प्रशासन विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ९ जुलाई २०१४ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIII OF 2014.

AN ORDINANCE

TO PROVIDE FOR RESERVATION OF SEATS FOR ADMISSION IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF
APPOINTMENTS OR POSTS IN THE PUBLIC SERVICES UNDER
THE STATE TO EDUCATIONALLY AND SOCIALLY BACKWARD
CATEGORY (ESBC) IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR THEIR
ADVANCEMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH
OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३, सन् २०१४ ।

महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) को उनकी उन्नति के लिये राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिये और तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य की नागरिकों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिये राज्य की आरक्षण और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की नीति महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वयन के अधीन है ;

और क्योंकि भारत में आरक्षण संकल्पना के जनक के रूप में जाने जानेवाले श्री राजर्षी शाहू महाराज ने १९०२ वर्ष में क्रमशः २६ जुलाई १९०२ और २ अगस्त १९०२ में करवीर संस्थान (कोल्हापूर) में सार्वजनिक रोजगार में सीटों के आरक्षण मुहैया करने के लिये दो अधिसूचनाएँ जारी की थी और जिससे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को भारत के संविधान में आरक्षण के लिये उपबंध करने के लिये प्रेरणा मिली थी और सन् १९०२ में की उक्त दो अधिसूचनाओं में पिछड़े वर्गों को आरक्षण का उपबंध किया गया था, जिसमें मराठा समुदाय को शामिल भी किया गया था ;

और क्योंकि तत्कालिन बम्बई सरकार के दिनांकित २३ अप्रैल १९४२ के संकल्प द्वारा मराठा और अन्य जातियों समेत लगभग २२८ समुदाय मध्यमवर्ग और पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित की गई थी और उक्त संकल्प की संलग्न अनुसूची में १४९ क्रमसंख्या में मराठा समुदाय को दर्शाया गया है ;

और क्योंकि मराठा आरक्षण का मामला वर्ष २००४ में महाराष्ट्र राज्य पिछड़े वर्ग आयोग को उनकी सिफारिशों के लिये निर्दिष्ट किया गया था और राज्य आयोग ने २८ जुलाई २००८ को अपनी २२ वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह कहा गया था कि “अन्य पिछड़े वर्ग” के प्रवर्ग में मराठा समुदाय को ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ;

और क्योंकि मंत्रिमंडल उप-समिति ने विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात्, मराठा समुदाय के शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर सांख्यिकी डाटा अपर्याप्त होने की अपनी रिपोर्ट देने के लिये मामला राज्य आयोग को वापस भेजा था और आरक्षण की विद्यमान संरचना को बाधा डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सकेगा या नहीं के बारे में अपनी राय देने के बारे में अनुरोध भी किया था ;

और क्योंकि राज्य आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बारंबार अनुरोध करने के पश्चात्, राज्य आयोग ने केवल २२ वीं रिपोर्ट पर महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ९ की उप-धारा (२) के अनुसार निर्णय लेने के लिये आग्रह किया था ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त की गई राणे समिति ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन से संबंधित सांख्यिकी डाटा पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया है और उसके पश्चात्, राज्य आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यमान आरक्षण को बाधा डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण के उपबंध करने के लिये अपनी टिप्पणी देने के लिये दुबारा अनुरोध किया था ;

और क्योंकि राज्य आयोग ने दिनांकित २० मई २०१४ के अपने पत्र द्वारा सरकार के राज्य आयोग की २२ वीं रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिये अनुरोध किया था ;

और क्योंकि उपर्युक्त पार्श्वभूमी को देखते हुए, यह विश्वास करने की गुंजाईश है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस मामले में निर्णय लेने के लिये अनिच्छुक था और अतः सरकार ने, अधिकाधिक एक दशक राह देखने के पश्चात्, निर्णय लेने का विनिश्चय किया है और सरकार ने २५ जून २०१४ को हुई अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में २२ वीं रिपोर्ट को अंशतः अस्वीकृत करने और महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ९ की उप-धारा (२) के आधार पर मराठा समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने से वह आरक्षण के लिये पात्र है इस कतिपय उपांतरणों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि राणे समिति द्वारा संग्रहित सामग्री और डाटा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार की यह राय है कि मराठा समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है और राज्य के अधीन सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है, अतः रोजगार में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आरक्षण आवश्यक है ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ का खंड (४), किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिये कोई विशेष उपबंध करने के लिये राज्य को समर्थ करता है ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ का खंड (५) नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उन्नयन के लिए, विधिद्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने के लिए

राज्य को समर्थ बनाता है, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न है।

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद १६ का खंड (४) नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियाँ या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध बनाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है, जो राज्य की राय में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४), १५(५), १६(४) और ४६ भी से भिन्न राज्य को अलग वर्ग का उपबंध करने के लिए भी सशक्त बनाते हैं।

और क्योंकि, महाराष्ट्र राज्य ने संविधान के अनुच्छेद १६ के खंड (४) के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निराधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़े प्रवर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, २००१ अधिनियमित किया है।

और क्योंकि, राणे समिति द्वारा संग्रहित सामुग्री और डाटा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार का विचार यह है कि मराठा समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है, और राज्य के अधीन सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है अतः उनके उन्नति के लिए विशेष उपबंध करना आवश्यक है।

और क्योंकि राज्य सरकार ने, सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात्, नवीन प्रवर्ग अर्थात् शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) सृजित करने का नीति निर्णय लिया है और ऐसे नवीन सृजित शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के लिये राज्य में लागू विद्यमान बावन प्रतिशत आरक्षण को बाधा डाले बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों में, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन ९ जून २०१४ को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण को छोड़कर अलग सोलह प्रतिशत आरक्षण होगा और उक्त प्रवर्ग में मराठा समुदाय को शामिल किया गया है ;

और क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं समेत निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो और भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में के आरक्षण को छोड़कर, राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियों या पदों में उनकी उन्नति के लिए राज्य में विद्यमान लागू बावन प्रतिशत आरक्षण को बाधा डाले बिना नया शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा प्रवर्ग (इएसबीसी) सृजित करने तथा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा प्रवर्ग और जिसमें इस प्रवर्ग के अधीन मराठा समुदाय समवेशित है के लिए पृथक सोलह प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने के लिए इस निमित्त ९ जून २०१४ को जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए विधि बनाने हेतु सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए) अध्यादेश, २०१४ कहलाए। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभण ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

२. (१) इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ।

(क) “ प्रवेश प्राधिकरण ” शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश संबंधी में तात्पर्य, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश के लिए जिम्मेवार शैक्षणिक संस्थाओं पर पर्यवेक्षीय और नियंत्रण की शक्तियाँ रखने वाले प्राधिकरण से है ;

(ख) “नियुक्ति प्राधिकरण” लोक सेवाओं तथा पदों के संबंधी में तात्पर्य, ऐसी सेवाओं या पदों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त किये गये प्राधिकरण से है ;

(ग) “सक्षम प्राधिकरण” का तात्पर्य, धारा ६ के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकरण से है ;

(घ) “शैक्षणिक संस्था” का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं से है जो सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाएँ समेत चाहे वह राज्य द्वारा सहायता या बिना सहायता प्राप्त हो सुसंगत महाराष्ट्र अधिनियमों द्वारा या के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय समेत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले से है ;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “निजी शैक्षणिक संस्थाओं” की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, उन संस्थाओं से है जिन्हें इस अध्यादेश में प्रवृत्त होने के पूर्व या प्रवृत्त या उसके पश्चात्, सरकार द्वारा रियायती दरों या किसी अन्य आर्थिक रियायतों में सरकारी भूमि में सहायता दी जाती है या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञप्ति प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है ;

(ङ) “शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी)” का तात्पर्य, ऐसे प्रवर्ग या नागरिकों के प्रवर्गों से है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग के नागरिकों तथा सरकार द्वारा समय - समय पर जिन्हें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) के रूप में घोषित किया गया है ;

(च) “स्थापना” का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण के किसी अधिकारी या विश्वविद्यालय या कंपनी, किसी निगम या सहकारी संस्था जिसमें, सरकार या किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्था द्वारा पूंजी शेयर है।

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं” की अभिव्यक्ति में, संस्थाओं या उद्योगों जिन्हें या तो इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने से पूर्व या पश्चात् सरकार द्वारा रियायती दरों या अन्य किसी आर्थिक रियायतों में सरकारी भूमि के प्ररूप में सहायता दी जाती है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञप्ति प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है वह भी सम्मिलित होगी ;

(छ) “सरकार” या “राज्य सरकार” का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है।

(ज) “विहित” का तात्पर्य, इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(झ) “लोक सेवाओं तथा पदों” का तात्पर्य, राज्य के कार्यों के साथ जुड़े हुए सेवाओं और पदों से है तथा सेवाओं और पदों समेत में—

(एक) स्थानिक प्राधिकरण ;

(दो) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन स्थापित सहकारी संस्था जिसमें सरकार शेयर धारक है ;

(तीन) केंद्र या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित बोर्ड या निगम या निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रणाधीन है या कंपनी अधिनियम, १९५६ या कंपनी अधिनियम, २०१३ में परिभाषित सरकारी कंपनी है ;

(चार) सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन शैक्षणिक संस्था जो सरकार समेत महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सहायता अनुदान प्राप्त करती है ; और

(पाँच) इस अध्यादेश के प्रारंभण दिनांक पर सरकार द्वारा जो आरक्षण लागू था और जो उप-खंड (एक) से (चार) के अधीन आवृत्त नहीं है के विषय में कोई अन्य स्थापना ;

(ज) “आरक्षण” का तात्पर्य, राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) को प्रवेश के लिए सीटों तथा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) के सदस्यों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण से है।

सन् २०६१
का महा.
२४।
सन् २०५६
का १।
सन् २०१३
का १८।

(२) इस अध्यादेश में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, किन्तु अपरिभाषित, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबादोश जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, २००१ और किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में वह क्रमशः समान अर्थों में निर्दिष्ट होंगे।

३. (१) यह अध्यादेश, राज्य के अधीन लोक सेवाओं में बनाए गए सभी सीधी भर्तियों, नियुक्तियों या पदों को लागू होगा, के सिवाय—

- (क) चिकित्सा, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में उच्च विशेष पदों ;
- (ख) अंतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले पदों ;
- (ग) चालीस-पैंतालीस दिनों की कालावधि से अनून अस्थायी नियुक्तियों; और
- (घ) किसी संवर्ग या श्रेणी में एकमात्र (अलग) जो पद है।

(२) यह अध्यादेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं समेत निजी शैक्षणिक संस्थाएँ चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त हो में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) के सीटों में प्रवेश के लिए लागू होगा।

(३) राज्य सरकार, क्रमशः धारा २ के खंड (घ) और (च) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित किसी सहायता की मंजूरी के लिए किसी शैक्षणिक संस्था या किसी स्थापना के साथ करार में प्रवेश करते या नवीकरण करते समय ऐसी शैक्षणिक संस्था या स्थापना के द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों के साथ अनुपालन के लिए शर्त सम्मिलित करेगी।

सन् २००४
का
महा. ८।

४. (१) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबादोश जनजाति, विशेष पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, २००१ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या किसी न्यायालय के आदेश या किसी प्राधिकरण में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अध्यादेश के अन्य उपबंधों के अध्याधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में, निजी संस्थों समेत, चाहे वह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, कुल सीटों के सोलह प्रतिशत, और सरकार के अधीन लोकसेवाओं में कुल नियुक्तियाँ और पदों के सीधा भर्ती में सोलह प्रतिशत, राज्य में शैक्षणिक और सामाजिक, रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) जिसमें मराठा समुदाय शामिल है, के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षित रखे जायेंगे :

शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय (ईएसबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों, राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्ति और पदों के लिए आरक्षण।

परंतु, उक्त आरक्षण इस निमित्त ९ जून २०१४ को जारी की गई सूचना के अनुसार, भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन राज्य निर्धारित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित रखे गये पदों के लिए लागू नहीं होगा।

(२) नवोन्नत वर्ग का सिद्धांत शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) को लागू होगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए “ नवोन्नत वर्ग ” अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सरकार के सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग द्वारा, जो व्यक्ति नवोन्नत वर्ग में आता है इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये साधारण या विशेष आदेशों, द्वारा यथा घोषित नवोन्नत वर्ग से है।

५. धारा ४ में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े आरक्षण प्रभावित प्रवर्ग (ईएसबीसी) से संबंधी छात्रों और सदस्यों के दावे अनारक्षित सीटों, नियुक्तियाँ या पदों के लिए जो अर्हता के आधार पर भरे जाएँगे, वह भी विचार में लिये जाएँगे और जहाँ ऐसे प्रवर्गों के छात्र या सदस्य अर्हता के आधार पर चयनित किये गए हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, नियुक्तियाँ या यथास्थिति पदों, किसी भी मार्ग से प्रभावित नहीं होंगे।

सक्षम प्राधिकारी।

६. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों और तद्धीन बनाए गये नियमों को कार्यान्वित करने के लिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित किया जाए ऐसे शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेंगे।

सरकार की निदेश देने की शक्तियाँ।

७. (१) सरकार, लोक हित में, आदेश में विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा इस अध्यादेश के अधीन समय-समय पर पूछताछ करने या समुचित कार्यवाहियाँ करने के निदेश सक्षम अधिकारी को देगी और सक्षम अधिकारी, जैसे कि विहित किया जाए ऐसे अवधि के अधीन, उसके द्वारा की गई पूछताछ या की गई कार्यवाहियों के परिणामों की रिपोर्ट सरकार को देगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, सक्षम अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, जैसे वह उचित समझें ऐसे निदेश देगी और ऐसे निदेश अंतिम होंगे।

आरक्षित रिक्तियों का अग्रनयन।

८. यदि किसी भर्ती वर्ष के संबंध में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के व्यक्तियों को लिए कोई आरक्षित रिक्ति भरी जानी बाकी है तो, ऐसे रिक्ति सीधे भर्ती के मामले में पाँच वर्षों तक अग्रनयीत की जायेगी :

परंतु, इस अध्यादेश के प्रारंभण के दिनांक को पदों को भरने के संबंध में यदि कोई सरकारी आदेश, संकल्प, परिपत्र और कार्यालयीन ज्ञापन प्रवृत्त है तब, वही सरकार द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहत किये जाने तक, प्रवृत्त बने रहेंगे और सरकार ऐसे सरकारी आदेशों, संकल्पों, परिपत्रों और कार्यालयीन ज्ञापनों का संशोधन करने में सशक्त होगी :

परंतु आगे यह की, इस अध्यादेश की धारा १७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकारी विभागों को एतद्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, सीधी भर्ती के लिये विहित किये गये पुनरिक्षित रोस्टर समेत जैसा कि आवश्यक समझे, इस आरक्षण के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिये सरकारी आदेश द्वारा सशक्त किया जायेगा :

परंतु यह भी कि, यदि मंजूर पद हर एक प्रवर्ग के लिये कम से कम एक पद आबंटित करना पर्याप्त नहीं होता है तब, आरक्षित पद, इस निमित्त विहित या उपांतरित किये गये सरकारी रोस्टर आदेशों या नियमों के अनुसरण में मूल चक्रानुक्रम द्वारा लागू करके भरे जायेंगे और तदनुसार रोस्टर बिंदू और आदेश या नियम पुनरिक्षित करने के लिये, सरकार को सशक्त किया जायेगा।

(२) जब, कोई रिक्ति उप-धारा (१) में यथा उपबंधित अग्रनयीत की गई है तो, वह उस भर्ती वर्ष में जिसमें वह अग्रनयीत की गई है, संबंधित व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे के सामने नहीं गिनी जायेगी।

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, ऐसी न भरी गयी रिक्तियों को भरने के लिये, विशेष भर्ती मुहिम शुरू कर सकता है और यदि ऐसी रिक्तियाँ ऐसी विशेष भर्ती मुहिम शुरू करने के बाद भी भरी नहीं जाती है तो, ऐसी रिक्तियाँ भरी जायेंगी जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया गया हो।

अध्यादेश का अनुपालन करने का दायित्व और शक्तियाँ।

९. (१) सरकार, लिखित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दायित्व के साथ, ऐसे प्राधिकारी के अधीन प्रत्येक प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अधिकारी को सौपेगी।

(२) सरकार, ऐसी रिक्तियाँ, प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी, ऐसी प्राधिकारी या अधिकारी को समुनुदेशित किये गये दायित्व का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिये ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को आवश्यक हो।

शास्ति।

१०. (१) कर्तव्य या दायित्व सुपुर्द किया गया कोई प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जो जानबूझकर इस अध्यादेश के प्रयोजन के उल्लंघन के या उसे विफल करने के आशय से कार्य करता है, तो दोषसिद्धी पर, नब्बे दिनों तक बढ़ाये जा सकने वाले कारावास या पाँच हजार रुपये तक बढ़ाये जा सकनेवाले जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(२) कोई भी न्यायालय, सरकार द्वारा इस निमित्त सरकार या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का सज़ान नहीं लेगा।

११. जब सरकार के ध्यान में यह बात आती है या ध्यान में लायी जाती है कि शैक्षणिक और अभिलेख मंगाने सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) संबंधी कोई व्यक्ति पर प्रवेश अधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों या तद्धीन निर्मित नियमों या इस निमित्त सरकारी आदेशों के अननुपालन के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वह किसी प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिलेख मंगा सकेगी और ऐसा समुचित आदेश पारित कर सकेगी जो उसे उचित प्रतीत हो।

१२. (१) सरकार, आदेश द्वारा, लोक सेवा और पदों की नियुक्ति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ, चयन, जाँच और विभाग समिति में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) चयन समिति में प्रतिनिधित्व से संबंधित अधिकारियों के नामनिर्देशन का उपबंध कर सकेगी।

(२) सरकार, आदेश द्वारा ऐसी आर्थिक या अन्य रियायत अनुदत्त कर सकेगी जो उसे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के हित में आवश्यक प्रतीत हो।

१३. इस अध्यादेश के उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई भी प्रवेश या नियुक्तियाँ शून्य होंगी। अनियमित नियुक्तियाँ शून्य होंगी।

१४. सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक होगा।

सन् १८६० का ४५। १५. इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए, सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ स्वीकार्य नहीं की जाएगी। सद्भावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण।

१६. इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करने वाले नहीं होंगे। इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अलावा होंगे।

१७. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों के निर्वहन के लिए नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि जिसमें यह रखा गया है उस सत्र में या के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करते हैं तो नियम, ऐसे विनिश्चय के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभाव हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

१८. इस अध्यादेश के उपबंध, ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगे जिसमें चयन प्रक्रिया इस अध्यादेश व्यावृत्ति के प्रारम्भण से पहले ही शुरू की गई है और ऐसे मामलों का निपटान विधि के उपबंधों और सरकारी आदेशों के अनुसार उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित थे।

स्पष्टिकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, चयन प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन,—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, साक्षात्कार शुरू हो चुका है, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर नियुक्ति की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा शुरू हो चुकी है।

(२) उस अध्यादेश के उपबंध, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों और ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगी जिसमें प्रवेश प्रक्रिया इस अध्यादेश के प्रारम्भण से पहले शुरू की गई है और ऐसे मामलों का निपटान विधि के उपबंधों और आदेशों के अनुसार उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित थे।

स्पष्टिकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी जहाँ,—

(एक) किसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है और ऐसी प्रवेश परीक्षा के लिये प्रक्रिया, यथास्थिति, शुरू हो चुकी है ; या

(दो) प्रवेश प्रक्रिया के आधार पर से अन्य प्रवेश के मामले में आवेदन पत्र भरने के लिये अंतिम दिनांक व्यपगत हो चुका है।

कठिनाई के
निराकरण की
शक्तियाँ।

१९. (१) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर आये हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हो ऐसी बात कर सकेगा जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, बनाये जाने के पश्चात्, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य, अल्पाधिकारवालों के लिए आरक्षण मुहैया करनेवाला अग्रणी राज्य है और नागरिकों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक और शैक्षणिक उन्नयन के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश हेतु आरक्षण और राज्य के अधीन की लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से महाराष्ट्र राज्य के अधीन है।

२. सन् १९०२ में भारत की आरक्षण संकल्पना का जनक जानेवाले राजश्री शाहू महाराज द्वारा सार्वजनिक रोजगार में सीटों का आरक्षण करने के लिए प्रारंभिक दो अधिसूचनाएँ जारी की गई थी। सन् १९०२ की उक्त अधिसूचनाओं में मराठा समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण मुहैया किया गया था। तत्कालीन, बम्बई सरकार द्वारा जारी किये गये दिनांक २३ अप्रैल १९४२ के संकल्प में, करीबन २२८ समुदायों को मध्यमवर्ग और पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया गया था जिसमें उसकी संलग्न सूची में क्रम संख्या १४९ पर मराठा समुदाय को दर्शाया गया है। महाराष्ट्र राज्य में, मराठा समुदाय संख्यात्मक रूप से बड़े पैमाने पर है, किन्तु, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के अवसर कम होने के कारण और राज्य की अधीन की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण समुदाय अधिक संख्या में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है।

३. भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ का खण्ड (४), नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है और उक्त अनुच्छेद का खण्ड ५, किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उन्नयन के लिए विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० का खण्ड १ और अनुच्छेद १६ का खण्ड ४ में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियाँ या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध बनाने के लिए राज्य को समर्थ बना सके, जो राज्य की राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

४. महाराष्ट्र राज्य ने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण] अधिनियम, २००१ (सन् २००४ का महा. ८) अधिनियमित किया था। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राणे समिति द्वारा सामग्री और डाटा के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार का दृष्टिकोण यह है कि, नागरिकों के वर्ग जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें राज्य के अधीन की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनके उन्नयन के लिए विशेष प्रबंध तुरंत करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने, सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद, नीति निर्णय लिया है कि, राज्य में प्रचलित लागू विद्यमान बावन प्रतिशत आरक्षण को बाधा डाले बिना भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड १ में निर्दिष्ट अल्पसंख्याक संस्थाओं से भिन्न निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेशों में, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, और राज्य के अधीन की लोकसेवाओं में की नियुक्तियाँ या पदों में, भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन इस निमित्त, दिनांक ९ जून २०१४ को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के निर्धारित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर, वहाँ सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के लिये अलग सोलह प्रतिशत का आरक्षण होगा। जिसमें मराठा समुदाय सम्मिलित होगा।

५. **क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, विधि बनाने के लिये कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित ९ जुलाई २०१४ ।

के. शंकरनारायणन्,

महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

प्रमोद टी. नलावडे,

शासन के सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती ललिता देठे,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।